

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1764

जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2022 को दिया जाना है

और अधिक परमाणु रिएक्टरों की स्थापना का प्रस्ताव

1764 श्री नरेश बंसल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में देश में कुछ परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस निर्णय से परमाणु ऊर्जा उत्पादन, जो वर्तमान में केवल दो प्रतिशत है, को कम से कम 11 प्रतिशत के वैश्विक औसत तक बढ़ाने में कितनी सहायता मिलेगी; और
- (घ) इससे भारत की क्षमता में कितनी वृद्धि हो सकती है तथा दस परमाणु रिएक्टरों को स्थापित करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

- (क) तथा (ख) जी, हां। सरकार ने शीघ्रगामी (फ्लोट) मोड में प्रत्येक 700 मेगावाट के दस (10) स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) की स्थापना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है। कैगा, कर्नाटक (कैगा-5 और 6); गोरखपुर, हरियाणा (जीएचएवीपी-3 और 4); चुटका, मध्य प्रदेश (चुटका-1 और 2) तथा माही बांसवाड़ा, राजस्थान (यूनिट 1 से 4) में रिएक्टरों की योजना बनाई गई है।
- (ग) इन रिएक्टरों के क्रमिक रूप से पूरा होने पर वर्ष 2031 तक नाभिकीय विद्युत क्षमता 7000 मेगावाट और बढ़ जाएगी। इस क्षमता वृद्धि के परिणामस्वरूप नाभिकीय ऊर्जा के हिस्से में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, यह उस समय अन्य स्रोतों से प्राप्त क्षमताओं की वृद्धि पर निर्भर है।
- (घ) इन रिएक्टरों (7000 मेगावाट) और वर्तमान में निर्माण / कमीशनन (8700 मेगावाट) के अधीन अन्य रिएक्टरों के क्रमिक रूप से पूरा होने पर, देश में संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता, वर्तमान 6780 मेगावाट से बढ़कर 22480 मेगावाट हो जाएगी। यह क्षमता वर्ष 2031 तक क्रमिक रूप से बढ़ने की आशा है।

\* \* \* \* \*